आधुनिक ऊर्जा तंत्र
नये उत्तर प्रदेश की पहचान

प्रगति पथ@12 वर्ष

विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के

उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 9 वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधार करते हुए विद्युत उत्पादन, वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा को नई दिशा दी है। 'सौभाग्य योजना' के माध्यम से लाखों घरों तक नि:शुल्क बिजली कनेक्शन पहुंचाए गये, वहीं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युत अवसंरचना को मजबूत बनाया गया है। ट्रांसफॉर्मर, सब-स्टेशन व विद्युत लाइनों के आधुनिकीकरण से बिजली आपूर्ति अधिक स्थिर और विश्वसनीय हुई है। साथ ही, सौर ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि कर प्रदेश को ग्रीन एनर्जी की ओर अग्रसर किया गया है। स्मार्ट मीटरिंग, सोलर पंप और डिजिटल सेवाओं के जरिए ऊर्जा क्षेत्र में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ी है।

पारेषण लाइन	उपकेन्द्र	उपलब्धता
60,858 स.कि.मी.	715 2,05,632 मे.वो.ए.	99.30 प्रतिशत

9 वर्षों में बेहतर हुई ऊर्जा की उपलब्धता

- 765 के.वी. उपकेन्द्र **07**
- 400 के.वी. उपकेन्द्र **45**
- 220 के.वी. उपकेन्द्र **173**
- 132 के.वी. उपकेन्द्र **490**
- **2 लाख** ट्रांसमिशन टावर
- **2,100** ट्रांसफार्मर
- **3.2 प्रतिशत** पारेषण हानियाँ
- **31,486** मेगावाट पीक डिमांड

- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत यूपी में सभी चिन्हित घरों का 100% विद्युतीकरण पूर्ण
- आर0डी0एस0एस0 योजना के अंतर्गत 2,51,487 छूटे हुए घरों का विद्युतीकरण पूर्ण
- प्रदेश में स्थानीय व्यवधान को छोड़कर निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति
- निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए 60 नये 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र ऊर्जीकृत एवं 1,109 विद्युत उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ी
- वर्ष 2024-25 के अंतर्गत 28 नये 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण और 576 नग 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्रों की विद्युत क्षमता वृद्धि का कार्य पूर्ण
- सिंचाई की सुविधा हेतु पूर्ण जमा योजना एवं मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजनांतर्गत वर्ष 2022 से वर्ष 2025 तक किसानों के 2.42 लाख निजी नलकूपों का संयोजन
- पीएम कुसुम योजना में किसानों को 96,128 से अधिक सोलर पंप आवंटित
- आर0डी0एस0एस0 योजना के अंतर्गत 59.17 लाख उपभोक्ताओं के संयोजन पर स्मार्ट मीटर लगे

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का एकीकृत कॉल सेंटर 1912

बिजली बिल राहत योजना के तहत पहली बार में मूल बकाये में भी छूट, बिजली चोरी के मामलों में राजस्व निर्धारण की धनराशि में छूट का प्राविधान

प्रदेश में विद्युत बिल बकाये में अद्यतन 30.99 लाख उपभोक्ताओं द्वारा पंजीकरण किया गया

- झटपट पोर्टल पर वर्ष 2025-26 में नवंबर 2025 तक 9,03,085 नये संयोजन निर्गत
- उपभोक्ताओं को घर बैठे नये संयोजन लेने और बिल जमा करने की ऑनलाइन सुविधा
- उपभोक्ता सेवा केंद, जन सेवा केंद्रों, स्वयं सहायता समूहों, राशन की दुकानों, विद्युत सखियों, मीटर रीडर के माध्यम से विद्युत बिल जमा करने की सुविधा
- बुंदेलखंड क्षेत्र के ग्रामीण निजी नलकूप विद्युत उपभोक्ताओं को एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थायी विद्युत संयोजन की सुविधा
- प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग हेतु सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन स्टेशनों हेतु लागू वर्तमान टैरिफ राज्य परिवहन के लिए भी हुआ अनुमान्य
- यूपी सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विद्युत उत्पादन हेतु एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ एमओयू
- ऊर्जा की आवश्यकता के अनुरूप अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु पारेषण तंत्र का सुदृढ़ीकरण

विकास की गति अपार - डबल इंजन सरकार

ADVERTORIAL